



CA-208

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश .

B.O.R.

3 JUL 2012

क्रमांक - 30-7/12
दिनांक 30-7-12
अन्तर्गत हस्ताक्षर

30-7-12

R-2706-II/12

रूपबाल तनय मौजी कुम्हार निवासी ग्राम बैसा
खास तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र०
वनाम निगरानीकर्ता
म०प्र०शासन प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू रा०सं० 1959 एवं संशोधित
अधिनियम 2012 अधिनस्थ न्यायालय अपर क्लेक्टर महोदय
टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र० के द्वारा पारित प्र०क्र० 21/
स्व०निग०/2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 28.1.2005
के विरुद्ध ।

आदेश
कार्यालय कर्मचारी, सागर सम्भाग,
सागर (म.प्र.)
महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

यह कि भूमि खसरा क्रमांक 542, 543, 550 रकबा 1.510 है जो स्थित
ग्राम बैसा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र० में है जिसपर निगराकार वर्ष 1984 के
पूर्व से कब्जा किये चला आ रहा है और भूमिहीन होने के कारण उसे तहसीलदार तहसील
बल्देवगढ़ द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दख्खरहित भूमि पर भूमिस्वामि
अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत भूमिस्वामी -
अधिकार प्रदान किये गये थे तदनुसार तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्र०क्र० 310/आ० 1984/95-96
में दिनांक 20.8.96 को अधिकार प्रदान किये गये थे जिसकी विना कोई सूचना दिये अनु
विभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ़ द्वारा प्र०क्र० 56/बी-121/99-2000 में दिनांक 25.
8.99 को प्रतिवेदन दिया और अपर क्लेक्टर महोदय द्वारा आलोच्य प्रकरण सुनवाई में
लिया गया। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय अपर क्लेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा दिनांक
28.1.2005 को तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.8.96 निरस्त कर
भूमि शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी
न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं

1/2/012

7/8/12

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2706-दो / 2012

जिला-टीकमगढ़

सरूपलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 21/स्व.निग./2003-04 में पारित आदेश दिनांक 28-01-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>